- 371 भवन हैं देशभर में आईजीबीसी की रेटिंग वाले
- 137 रिहायशी इमारतें एवं टाउनशिप प्रोजेक्ट
- 219 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिल्डिंग हैं
- 15 इमारतें औद्योगिक इकाइयों की
- 73 इमारतों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर
- 26 भवनों के साथ दूसरे स्थान पर तमिलनाडु
- एक भी इमारत मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं

ग्रीनरी सही, ग्रीन बिल्डिंग नहीं

प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए जहां देश के अनेक राज्यों में पर्यावरण हितैषी ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा तेजी से अपनाई जा रही है, वहीं मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इस मामले में पिछड़ते दिख रहे हैं। भारत में पर्यावरण हितैषी भवनों का मूल्यांकन करने वाली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) और ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटिड हैबिटेट एसेसमेंट (गृहा) के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। देशभर में पिछले दस साल में आईजीबीसी की रेटिंग वाले 371 और गृहा की रेटिंग वाले 11 भवनों में से एक भी भवन इन दो राज्यों में नहीं है।

अजय गर्ग >> मुंबई

ग्रीन बिल्डिंग के मामले में महाराष्ट्र व तमिलनाडु सबसे आगे चल रहे हैं। आईजीबीसी की रेटिंग वाले 371 भवनों में से 219 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के हैं जिनमें होटल व कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं, 137 रिहायशी इमारतें एवं टाउनशिप प्रोजेक्ट हैं, जबकि बाकी 15 इमारतें औद्योगिक इकाइयों की हैं। रिहायशी एवं औद्योगिक भवनों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 73 भवन हैं, जिन्हें पर्यावरण हितैषी इमारत माना गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां 26 भवनों का प्रमाणन हुआ है। व्यावसायिक भवनों में सर्वाधिक 47 भवन तमिलनाडु और 45 महाराष्ट्र में हैं, जबकि कर्नाटक एवं आंध्रप्रदेश में ऐसे क्रमशः 28 व 23 भवन हैं।

आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में ग्रीन बिल्डिंग को लेकर सबसे अधिक जागरूकता है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) भी इस मामले में बहुत आगे नहीं हैं। एनसीआर में आईजीबीसी की ओर से प्रमाणित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवन केवल 37 हैं, जबकि औद्योगिक एवं रिहायशी भवनों की संख्या 8 ही है। इन 45 भवनों में से भी करीब 80 फीसदी दिल्ली की सीमा में न होते हुए हरियाणा के गुड़गांव एवं फरीदाबाद और उत्तरप्रदेश के नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हैं।

क्या है ग्रीन बिल्डिंग

ग्रीन बिल्डिंग असल में वातावरण के प्रति जिम्मेदार वो इमारत है जिसे बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जा एवं साधनों का कम दोहन हो, जिसके रखरखाव में पर्यावरण पर कम से कम बोझ पड़े और जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हो। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा टेरी द्वारा संयुक्तरूप से विकसित गृहा नामक एजेंसी के अलावा सीआईआई द्वारा वर्ष 2001 में स्थापित आईजीबीसी ऐसे भवनों को रेटिंग देती है। आईजीबीसी के पास दो तरह की रेटिंग है- रिहायशी एवं औद्योगिक भवनों को आईजीबीसी की रेटिंग दी जाती है, जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए लीडरशिप इन एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन (लीड) नामक अमेरिकी एजेंसी के मानकों पर बनाई गई लीड इंडिया-2011 की रेटिंग दी जाती है।

गुजरात में पहली सरकारी ग्रीन बिल्डिंग को गोल्ड रेटिंग

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गांधीनगर स्थित पर्यावरण भवन देश की पहली ऐसी सरकारी इमारत हो गया है जिसे इस साल जनवरी में आईजीबीसी ने पर्यावरण हितैषी भवन के रूप में लीड इंडिया-2011 प्रमाणपत्र दिया है। इस भवन की डिजाइन कन्सल्टेंट एवं आईजीबीसी की कार्यकारी समिति की सदस्य माला सिंह ने बताया कि यह भवन गत अप्रैल में बनकर तैयार हुआ था और इसे लीड इंडिया-2011 की गोल्ड रेटिंग हासिल हुई है।

मध्यप्रदेश में मंत्रालय एनेक्सी से होगी शुरुआत

मध्यप्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग के कांसेप्ट पर सरकार राज्य मंत्रालय भवन की एनेक्सी बनाते वक्त काम करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट ऊर्जा की खपत कम करता है लेकिन यह खर्चीला है। सरकार एनेक्सी बिल्डिंग बनाकर लोगों को इस बारे में प्रेरित करेगी। मलैया ने कहा कि वैसे भी इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईएसआई की तरह संस्था है। ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा पाने के लिए लोगों को खुद ही पहल करना होगी। अभी इंदौर के कुछ बिल्डर और डेवलपर्स ने काउंसिल को आवेदन किया है।